

### ग्रसाधारण

# EXTRAORDINARY

भाग I-- खभ्य 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

# PUBLISHED BY AUTHORITY

ਲੌਂ≎ 100] No. 190ì

- ---

नई बिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 1970/स्मेट 15, 1892

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 1970/JYAISTHA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या वी जाती है जिससे कि यह झलग संकलत के रूप में रका जा सके

Separate paging is given to this Part in ord r that it may be filed as a separate compilation

### MINISTRY OF FINANCE

#### RESOLUTION

New Delhi, the 4th June 1970

- No. F. 7(25)-E.III(A)/69.—The Government of India have decided to make the following amendments to the Resolution No. F. 7(25)-E.III(A)/69 dated the 23rd April 1970, setting up the Pay Commission.
- 2. For the existing sub-para (vii) of para 2, the following shall be substituted namely:—  $\cdot$ 
  - (vii) having regard to all relevant factors, the Commission may, while enquiring into the level of minimum remuneration, examine the Central Government employees' demand for a need-based minimum wage, which is based on the recommendations of the 15th Indian Labour Conference.
  - For the existing para 4, the following shall be substituted, namely:—
    - 4. In case the need for consideration of relief of an interim character arises during the course of deliberations of the Commission, the Commission may consider the demand for relief of an interim character and send reports thereon. In the event of the Commission recommending any interim relief, the date from which this relief

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India; State Governments/Administrations of Union Territories and all other concerned,

P. GOVINDAN NAIR. Secy.

## विश मंत्राला

## संकरप

नई दिल्ली, 4 ज्न, 1970

सं० फा० 7(25)—ई III (ए)/69.—वेतन श्रायोग की नियुक्ति से सम्बन्धित, 23 शर्षेल 1970 के संकल्प सं० फा० 7(25)—ई III(ए)/69 में भारत सरकार ने निम्नलिखित संशोधन करने का निर्णय किया है ;

- 2. पैराग्राफ 2 के विद्यमान उप-पैराग्राफ ( ${
  m vii}$ ) के स्थान पर निस्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा:---
  - २ (vii) स्यूनतम पारिश्रमिक स्तर सम्बन्धी जांच करते समय, सभी संगत तथ्य को ध्यान में रखते हुए, श्रायोग, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की, श्रावक्यकता प्र ग्राश्चारित न्यूनतम वेतन की मांग की जांच कर सकता है, जो 15वें भारतीय अस सम्मेलन की सिफारिशों पर श्राधारित है।
  - विद्यमान पैराग्राफ 4 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायगा :---
  - 4. ग्रायोग के विचार विमर्श के दौरान यदि अन्तरिम किस्म की राहत पर विचार करने की ग्रावश्यकता महसूस की जाय तो ग्रायोग अन्तरिम किस्म की राहत की मांग पर विचार कर सकता है ग्रीर उस पर रिपोर्ट भेज सकता है। यदि ग्रायोग किसी ग्रन्तरिम राहत की सिफारिश करे तो वह यह सुझाव भी देगा कि उक्त राहत किस तारीख से दी जाय।

श्रादेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपल में प्रकाशित किया जाय । यह श्रादेश भी दिया जाता है कि इस संबल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागः, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों भीर ग्रन्य सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को भेजी जाय ।

> पी० <mark>गोबिन्दन्</mark> नायर, स**ष्टिन, भा**रत **सर**कार ।